200 करोड़ रुपये की लागत से होगा आठ नए सरकारी स्कूलों की इमारतों का निर्माण। प्रत्येक स्कूल में 52 से लेकर 106 कमरे होंगे। निर्माण कार्य एक साल के अंदर पूरा किया जाएगा। दिल्ली सरकार की खर्च एवं व्यय समिति ने इसकी मंजूरी दे दी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 31 जुलाई 2019

इंडिया गेट के पास सूर्यास्त से आधे घंटे पहले तेज संगीत बजाने पर पाबंदी

जासं, नई दिल्ली : नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एनडीएमसी) ने इंडिया गेट और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के आस-पास सूर्यास्त से आधे घंटे पहले तेज संगीत नहीं बजाने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष फरवरी में शुरू हुए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में प्रतिदिन सूर्यास्त से पहले रिट्रीट समारोह का आयोजन होता है। 15 मिनट तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शक भी पहुंचते हैं। एनडीएमसी ने रिट्रीट का हवाला देते हुए कहा कि इस दौरान स्मारक के आसपास संगीत या तेज आवाज की वजह से रिट्रीट कार्यक्रम में बाधा पहुंचती है। इसलिए आयोजकों को निर्देश दिया जाता है कि इंडिया गेट और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के आसपास सूर्यास्त से ठीक करीब आधे घंटे पहले तेज संगीत न बजाएं। एनडीएमसी ने सलाह दी कि है आयोजक इसके लिए स्मारक के पदाधिकारियों से भी समन्वय कर सकते हैं। 40 एकड़ में फैले इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को आजादी के बाद से विभिन्न युद्धों में शहीद होने वाले 22,600 से अधिक सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है। एनडीएमसी ने यह आदेश केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के आग्रह के बाद दिया है।

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के सात नए रूटों को कैबिनेट की मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा को मिल रही सफलता को देखते हुए कैबिनेट ने मंगलवार को सात और रूटों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बुजुर्ग लोगों की भारी मांग पर नए रूट और जोड़े गए हैं। ये सातों रूट दक्षिण के प्रमुख तीर्थ स्थलों से संबंधित हैं। साथ ही सरकार तीर्थ यात्रा पर जाने वाले बुजुर्गों एवं उनके अटेंडेंट के रहने की व्यवस्था भी एसी होटलों में करने जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस यात्रा के तहत पहली ट्रेन अमृतसर और वैष्णो देवी गई थी, इसका अनुभव बहुत अच्छा रहा। यहां गए बुजुर्गों और अन्य लोगों से प्राप्त हुए सुझावों को सरकार ने इस योजना के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस योजना में पांच रूट हैं, लेकिन अब सात रूट और जोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा वर्तमान अजमेर-पुष्कर रूट में हल्दी घाटी को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा किसी भी इलाके के विधायक के अलावा सरकार का कोई भी मंत्री और तीर्थ यात्रा विकास समिति के चेयरमैन भी यात्रा पर जाने वाले बुजुर्गों के निवास से संबंधित प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं।

कैबिनेट ने अदालत परिसरों में 144 अस्थायी निर्माण की दी मंजूरी : दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली की अदालतों में 144 अस्थायी निर्माण व पोर्टा केबिन बनाने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। इन्हें अलग-अलग अदालत परिसरों में जरूरत के हिसाब से बनाया जाएगा। ये निर्माण तीस हजारी, कड़कड़डूमा व साकेत कोर्ट में किए जाएंगे। ये निर्माण दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर बनाई गई कमेटी के सुझाव के आधार पर होंगे।

ये हैं सात नए रूट

रूट	यात्रा के लिए संभावित वक्त
दिल्ली-रामेश्वरम- मदुरै-दिल्ली	आठ दिन
दिल्ली-तिरुपति-दिल्ली	सात दिन
दिल्ली-द्वारिकाधीश-नागेश्वर-दिल्ली	छह दिन
दिल्ली-जगन्नाथ पुरी-कोणार्क-भुवनेश्वर- दिल्ली	सात दिन
दिल्ली-शिरडी-शनि शिंगलापुर- दिल्ली	पांच दिन
दिल्ली-उज्जैन-ओंकारेश्वर-दिल्ली	छह दिन
दिल्ली-बोधगया-सारनाथ	सुनिश्चित करना है

आप सरकार ने मुफ्त यात्रा योजना को ठंडे बस्ते में डाला : भाजपा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा ने मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा को लेकर आप सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उसका कहना है कि सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सरकार का मकसद सिर्फ योजना को प्रचारित करके महिलाओं का वोट हासिल करना है। यही कारण है कि इस योजना को आज तक स्वीकृति के लिए कैबिनेट के समक्ष नहीं लाया गया है। आप सरकार ने बिना किसी वित्तीय, तकनीकी व व्यावहारिक पहलुओं पर विचार किए इस योजना को प्रचारित किया जिससे कि उसे इसका राजनीतिक लाभ मिल सके।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने मेट्रो में मुफ्त यात्रा को लेकर दिल्ली की जनता से 30 जून तक सुझाव मांगे थे। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि एक माह बीत जाने के बाद भी जनता के सुझावों को लेकर वह चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संसद में स्पष्ट कर चुकी है कि उसे दिल्ली सरकार से मेट्रो में महिलाओं को निशुल्क यात्रा को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री तक ने इस योजना को स्वीकृति नहीं दी है।

10वीं और 12वीं कक्षा में नहीं बदले जाएंगे विषय

- सीबीएसई ने किया स्पष्ट, सिर्फ छात्र या अभिभावक के चाहने पर नहीं मिलेगी अनुमति
- 15 जुलाई से पहले विषय बदलने के आग्रह पर किया जा सकता है विचार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने जुड़े स्कूलों को स्पष्ट किया है कि 10वीं और 12वीं कक्षा में विषय बदलने का कोई आग्रह इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि छात्र या अभिभावक उस विषय की पढ़ाई की व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। सीबीएसई के अनुसार, 10वीं और 12वीं कक्षाएं दो वर्षीय पाठ्यक्रम हैं। स्कूलों से उम्मीद की जाती है कि वे छात्र-छात्राओं को नौवीं और 11वीं कक्षाओं में ऐसे विषय चुनने की सलाह दें, जिसे वे अगली कक्षा में भी जारी रख सकें और ये विषय स्कूल में भी उपलब्ध हों।

सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं में विषय बदलने के आवेदनों से निपटने के लिए स्कूलों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की हैं। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जब विद्यार्थी 10वीं और 12वीं कक्षा में आते हैं तो विभिन्न आधार पर विषय बदलना चाहते हैं। संशोधित नियमों के तहत, विषय बदलने का कोई भी आग्रह केवल उस स्थिति में स्वीकार किया जाएगा, जब यह शैक्षणिक सत्र में 15 जुलाई से पहले किया गया हो। अधिकारी के मुताबिक किसी भी तरह से सीबीएसई की ओर से विषय बदलने के लिए ऐसा कोई आग्रह स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें कहा जाए कि अभिभावक अध्ययन के लिए व्यवस्था खुद कर लेंगे। अब लगभग सभी विषयों का आंतरिक आकलन होता है और स्कूलों को विद्यार्थियों के आंतरिक आकलन में प्रदर्शन की जानकारी देनी होगी।

प्रक्रिया निर्धारित की गई : अभिभावकों का विषय बदलने का आग्रह दिए गए एक निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। इसके साथ पिछली कक्षा का अंक पत्र (यदि स्कूल बदला नहीं है), यदि स्कूल बदला है तो अंक पत्र और स्थानातंरण प्रमाण पत्र और सरकारी अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आग्रह मिलने के बाद स्कूल को अपने स्तर पर तय करना है कि क्या विषय बदलने की वजह सही है? नया विषय स्कूल में उपलब्ध है या नहीं।

दुर्घटना पीड़ित के इलाज से इन्कार पर निजी अस्पताल पर होगी सख्त कार्रवाई

दो टूक ▶ मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा– इलाज के बिल का भुगतान करेगी सरकार

इसका मकसद पीड़ित को फौरन मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना है

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी है कि दुर्घटना में घायल को कोई निजी अस्पताल इलाज से मना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि दुर्घटना में घायल के इलाज पर आने वाले खर्च का बिल देने पर निजी अस्पताल को पूरा भुगतान दिल्ली सरकार करेगी। केजरीवाल ने इस मामले को लेकर दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को निजी अस्पतालों की बैठक बुलाई। जिसमें उन्होंने साफ किया कि इस बारे में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

बैठक के बाद प्रेसवार्ता कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली की सीमा के अंदर अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है या कोई एसिड अटैक होता है अथवा कोई बर्न इंजरी (जल जाने की कोई घटना) होती है तो उसका तुरंत इलाज कराना बहुत

दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। जागरण

जरूरी होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में कहा गया है कि पहले एक घंटे में अगर उसको मेडिकल की सुविधा मिल जाए तो दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की जान बचने के आसार काफी ज्यादा रहते हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई आदेश भी हैं जिनमें कहा गया है कि अगर किसी ऐसे पीड़ित को आप अस्पताल लेकर जाते हैं तो कोई भी अस्पताल इलाज करने से मना नहीं कर सकता। लेकिन, ऐसा देखा गया है कि कई बार निजी अस्पताल कोई न कोई बहाना बनाकर इलाज के लिए मना कर देते हैं। निजी अस्पताल वाले इसलिए इलाज करने से बचते हैं कि इसका बिल कौन देगा। दुर्घटना के शिकार व्यक्ति का बीमा है भी या नहीं। केजरीवाल ने कहा हम चाहते हैं कि ऐसे हादसों में जो भी पीड़ित हों उनको तुरंत मेडिकल की सुविधा मिले।

हम चाहते हैं कि दुर्घटना के आसपास मौजूद लोग दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले कर जाएं। वह अस्पताल चाहे कितना भी बड़ा हो। उसके इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। यह योजना फरवरी 2018 में लागू हुई थी। फरवरी 2018 से लेकर अप्रैल, 2019 के बीच इस 14 महीने में 2501 लोगों को अस्पताल ले जाकर जान बचाई जा चुकी है। कोई अस्पताल अगर मना करेगा तो दिल्ली सरकार उस अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने से भी नहीं हिचकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में एक और भी बहुत दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। दिल्ली सरकार ने स्कीम निकाली थी कि जो भी व्यक्ति दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अस्पताल ले जाएगा उसको 2 हजार रुपये का पुरस्कार मिलेगा। अभी तक 2501 मामले आए, मगर अस्पताल लेकर जाने वालों ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। अभी तक 100 से भी कम लोगों ने यह पुरस्कार लिया है।

आम्रपाली मामले में प्राधिकरण दाखिल करेगा पुनर्विचार याचिका

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

आम्रपाली बिल्डर मामले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। इसकी तैयारी हो चुकी है। यह याचिका आम्रपाली मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दाखिल की जाएगी। ताकि अगली सुनवाई में इसे भी शामिल कर लिया जाए। प्राधिकरण आम्रपाली बिल्डर पर अपनी बकाया रकम वसूलना चाहता है।

आम्रपाली पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का 3680 करोड़ रुपये बकाया है। प्राधिकरण ने पांच परियोजनाओं के लिए बिल्डर को 305 एकड़ जमीन आवंटित की थी। बिल्डर ने प्राधिकरण को केवल 376 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया है। बिल्डर से बकाया रकम वसूलने के लिए प्राधिकरण की पूरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों को राहत देते हुए आम्रपाली बिल्डर की परियोजनाओं में फंसे फ्लैटों को एनबीसीसी (नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन) को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खाते में कुछ नहीं आया है। अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बिल्डर की जिन संपत्तियों को बेचा जाएगा, उसके अलावा कोई ऐसी बड़ी संपत्ति नहीं है, जिससे प्राधिकरण अपनी बकाया रकम की वसूली कर सके। बिल्डर की शेष संपत्ति से केवल तीन सौ से चार सौ करोड़ रुपये मिलने की ही उम्मीद है। इसमें बैंक भी हिस्सेदार होगा, जिसने बिल्डर को ऋण दे रखा है।

दो अधिकारी गिरफ्तार

नई दिल्ली : आम्रपाली बिल्डर्स के दो प्रमुख अधिकारियों को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार किया है। सोमवार शाम गिरफ्तार किए गए अधिकारी चंद्र प्रकाश वाधवा (सीएफओ) और आम्रपाली समूह की कंपनियों के अनिल मित्तल (स्टेटरी ऑडिटर) हैं। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि दोनों को अपने ज्ञात व्यक्तियों व रिश्तेदारों को उन फर्जी कंपनियों में निदेशक और प्रमुख प्रबंधन पदों के रूप में नियुक्त करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें घर खरीदारों के निवेश किए गए पैसों को डायवर्ट करने के उद्देश्य से बनाया गया था। दोनों ने अपने ज्ञात व्यक्तियों व रिश्तेदारों को उन कंपनियों में नियुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्राधिकरण को शासन से भी फटकार मिली है। इसके बाद प्राधिकरण का बिल्डरों को लेकर रुख सख्त हो गया है। आम्रपाली बिल्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई नौ अगस्त को होनी है। प्राधिकरण की कोशिश है कि इससे पहले ही याचिका दाखिल कर दी जाए, जिससे अगली सुनवाई में कोर्ट उसकी याचिका को भी शामिल कर ले और प्राधिकरण के हक में कोई बात बन जाए।

हैप्पीनेस उत्सव में शामिल हुए चार राज्यों के शिक्षा मंत्री

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : हैप्पीनेस करिकुलम के एक वर्ष पूरा होने पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सर्वोदय कन्या स्कूल आरके पुरम और सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल नानकपुरम में हैप्पीनेस उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्सव में पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री आर कमलकानन, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी मणिपुर के शिक्षा मंत्री टोकछोम राधेश्याम, नागालैंड के शिक्षा मंत्री तोकुघा सुखलू प लद्दाख एजुकेशन काउंसिल के एक्सक्यूटिव कोंचोक स्टेनजिन शामिल हुए। दल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ उत्सव में पहुंचे सभी लोगों ने बच्चों से बातचीत की और हैप्पीनेस क्लास की खूबियों को करीब से जाना।

लद्दाख एजुकेशन काउंसिल के एक्सक्यूटिव कोंचोक स्टेनजिन ने दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था का प्रयास वह लद्दाख में भी करने का प्रयास करेंगे। वहीं पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री आर कमलकानन ने भी इस तरह की क्लास की सराहना करते हुए कहा कि वह दिल्ली सरकार के साथ मिलकर पुडुचेरी में भी यही प्रणाली लागू करने पर विचार कर रहे हैं। अगले शैक्षणिक सत्र में, हम निश्चित रूप से इसको लागू करेंगे। इसके लिए बहुत जल्द दोनो सरकारों के बीच एमओयू फाइनल हो सकता है। प्रभुराम चौधरी ने भी इसकी सरहाना की और अपने राज्य में इसे लागू करने की बात कही।

अभी न संभले तो हेपेटाइटिस से बड़ी समस्या होगी फैटी लिवर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मौजूदा समय में लिवर से जुड़ी बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है वायरल हेपेटाइटिस। देश में यह एक बड़ी समस्या है। खासतौर पर हेपेटाइटिस बी व सी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है, लेकिन शराब के सेवन व जीवनशैली में आए बदलाव से फैटी लिवर की भी समस्या तेजी से बढ़ रही है। यदि लोग अभी सचेत न हुए तो आने वाले दिनों में अमेरिका की तरह देश में भी हेपेटाइटिस से बड़ी समस्या फैटी लिवर की होगी। यह बातें एम्स में हेपेटाइटिस पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में सामने आईं, जहां डॉक्टरों ने कहा कि जो लोग शराब नहीं पीते उनमें भी मोटापे के कारण फैटी लिवर (नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर) की समस्या देखी जा रही है।

एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर की बीमारी का बढ़ना चिंता का विषय है। इसका कारण मोटापा, गलत खानपान व व्यायाम नहीं करना है। संस्थान के गैस्ट्रोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शालीमार ने कहा कि शराब का सेवन तेजी से बढ़ा है। दिल्ली में यह सरकार के लिए राजस्व का बड़ा जरिया है, जबकि इसका सेवन लिवर के लिए खतरनाक है। इससे लिवर खराब होने पर 70 फीसद लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा लोग व्यस्त दिनचर्या के कारण व्यायाम नहीं करते। लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहने व गलत खानपान के कारण फैटी लिवर की समस्या बढ़ रही है। इससे बचाव के लिए सभी को प्रतिदिन 45 मिनट व्यायाम जरूर करना चाहिए।

सरकारी कंपनियां बनाएं हेपेटाइटिस का टीका : एम्स के गैस्ट्रोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉ. अनूप सराया ने कहा कि हेपेटाइटिस बी मां से बच्चों में फैलती है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाती है, लेकिन संस्थागत प्रसव 70 फीसद होने के बावजूद 2015 में सिर्फ 45 फीसद बच्चों को ही टीका लग पाया। इसका मतलब यह हुआ कि अस्पताल में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को भी टीका नहीं लग पाता। सरकार को टीका निजी कंपनियों से खरीदने के बजाय इसे सरकारी कंपनियों द्वारा बनाने पर ध्यान देना होगा क्योंकि जन्म से 12 घंटे के अंदर टीका लग जाना चाहिए। यदि किसी कारण वश ऐसा नहीं होता तो 72 घंटे के अंदर तो हर हाल में टीका लगना चाहिए। इससे हेपेटाइटिस बी की रोकथाम की जा सकती है।

सेना के डॉक्टर का रेलवे ट्रैक पर मिला शव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सेना के डॉक्टर दिवाकर पुरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव सोमवार को सब्जी मंडी इलाके में रेलवे ट्रैक पर दो हिस्सों में पड़ा मिला। पुलिस इसे खुदकशी का मामला मान रही है, जबकि परिजनों ने हत्याकर शव ट्रैक पर फेंके जाने की आशंका जताई है। लखनऊ में दो महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह रविवार को श्रमजीवी एक्सप्रेस में दिल्ली के लिए बैठे थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है।

कैप्टन डॉ. दिवाकर पुरी (26) अपने परिवार के साथ दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-17 में रहते थे। उनके घर में माता-पिता के अलावा एक छोटा भाई है। पिता जीएल पुरी द्वारका स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च सेंटर में अकाउंटेंट हैं। छोटा भाई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। दिवाकर का करीब ढाई वर्ष पहले आर्मी में डॉक्टर के पद पर चयन हुआ था। उनकी पहली तैनाती राजस्थान के सूरतगढ़ में थी। वहां से उन्हें करीब दो महीने पहले सात सप्ताह की एक ट्रेनिंग के लिए लखनऊ भेजा गया था। यहां ट्रेनिंग पूरी कर वह रविवार को दिल्ली आने के लिए श्रमजीवी एक्सप्रेस में सवार हुए थे। पुलिस के मुताबिक सोमवार को दिन में 11.20 बजे सदर बाजार के रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा होने की उन्हें सूचना मिली।

कैप्टन डॉ. दिवाकर पुरी। सौजन्य : परिजन

शव रेलवे यार्ड से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर दो हिस्सों में पड़ा था। घटनास्थल पर ही पुलिस को एक बैग मिला। उसमें रखे पहचान पत्र से शव की पहचान डॉक्टर दिवाकर पुरी के रूप में हुई।

इसके बाद पुलिस ने परिजनों को जानकारी देकर शव का पोस्टमार्टम कराया। जांच में पुलिस को पता चला है कि कैप्टन श्रमजीवी एक्सप्रेस के कोच एच-1 में सफर कर रहे थे। ट्रेन जब दिल्ली स्टेशन पर पहुंची तो वह सो रहे थे। उन्हें अटेंडेंट वीरेंद्र रमन ने बताया कि ट्रेन दिल्ली पहुंच गई है। इसके बाद वह चला गया। माना जा रहा है कि वह अपने दो बैग छोड़कर ट्रेन से उतरकर पैदल रवाना हो गए। वहीं ट्रेन जब यार्ड में पहुंची तो अटेंडेंट ने लावारिस बैग देख इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दी। यह बैग भी जांच में दिवाकर के ही मिले। पुलिस फिलहाल इसे आत्महत्या मानकर मामले की जांच कर रही है। घटना की जानकारी के लिए रेलवे स्टेशन व आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।

दिवाकर के पिता जीएल पुरी का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। खुदकशी जैसा कदम वह कभी नहीं उठा सकते थे। यदि उन्हें कोई परेशानी होती तो वह जरूर बताते। उन्होंने पुलिस को बताया कि बेटे के ट्रेन में सवार होने पर उन्होंने कई बार फोन किया था, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। ट्रेन के दिल्ली पहुंचने पर परिजन स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन उनका फोन नहीं उठा और न ही उनकी मुलाकात हो सकी। इस बीच करीब छह घंटे तक स्टेशन और आसपास के इलाके में परिजन उनकी तलाश करते रहे। इसी बीच पुलिस द्वारा दिवाकर का शव ट्रैक पर मिलने की सूचना उन्हें मिली।

प्राथमिक जांच में सेना के अधिकारी द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। सीसीटीवी कैमरे आदि से घटना की सत्यता का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

-दिनेश कुमार गुप्ता, उपायुक्त, रेलवे पुलिस

हर-हर महादेव...

मंगलवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर पारदेश्वर धाम शिव हरि मंदिर में जलाभिषेक करते श्रद्धालु। ध्रुव कुमार

रास्ता साफ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े तेवर के बाद शुरू हुई तैयारी, एक माह में पूरा होगा पहले चरण का काम, 25 करोड़ होंगे खर्च

यमुना एक्सप्रेस वे से नीचे नहीं गिरेंगे वाहन, लगेंगे क्रैश बीम बैरियर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े तेवर और जेपी इंफ्राटेक की नानुकर के बाद आखिरकार यमुना एक्सप्रेस-वे पर आइआइटी के सुझावों को लागू करने का रास्ता साफ हो गया। एक माह में पहले चरण का कार्य पूरा होगा। एक्सप्रेस-वे पर ब्रिज की जगहों पर सड़क के दोनों ओर क्रैश बीम बैरियर लगेंगे। तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होने के बावजूद ब्रिज से नीचे नहीं गिरेंगे। इन कार्यों पर करीब 25 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यमुना प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा निगरानी समिति के आदेश पर आइआइटी दिल्ली से एक्सप्रेस वे का सुरक्षा ऑडिट कराया था। आइआइटी ने अपनी रिपोर्ट में एक्सप्रेस-वे पर सफर को सुरक्षित बनाने एवं हादसे रोकने के लिए कई अहम सुझाव दिए है। आगरा क्षेत्र में एक्सप्रेस-वे पर रोडवेज हादसे के बाद इन सुझावों को लागू करने के लिए यमुना प्राधिकरण एवं एक्सप्रेस वे का संचालन कर रही कंपनी जेपी इंफ्राटेक पर दबाव काफी बढ़ गया है। पहले चरण पर छह कार्य को पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में

ग्रेटर नोएडा स्थित यमुना एक्सप्रेस वे। जागरण

जेपी इंफ्राटेक को यमुना एक्सप्रेस वे पर आइआइटी के सुझावों को हर हाल में लागू करना होगा। पहले चरण के कार्यों को एक माह में पूरा करने का समय दिया गया है। अगले माह से यह कार्य शुरू हो जाएगा।

-डा. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण

मेडियन का काम शुरू होगा। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक एक्सप्रेस वे के मेडियन पर कर्व स्टोन को हटाकर क्रैश बीम बैरियर लगेंगे।

ब्रिज वाले स्थानों पर लगेंगे क्रैश बीम बैरियर : यमुना एक्सप्रेस वे 41 स्थानों पर ब्रिज बने हैं। इन जगहों पर एक्सप्रेस वे की दोनों सड़कों के बीच दूरी है। तेज रफ्तार वाहन असंतुलित होकर दोनों सड़कों की खाली जगह से नीचे गिरकर हादसाग्रस्त हो चुके हैं। आगरा क्षेत्र हादसे में रोडवेज बस भी दोनों सड़कों की बीच में खाली जगह से नीचे बह रहे नाले में गिरी थी। इस तरह के हादसे रोकने के लिए क्रैश बीम बैरियर लगाए जाएंगे। तेज रफ्तार वाहन अगर अनियंत्रित होकर क्रैश बीम बैरियर से टकराता है तो वह दोनों सड़कों के बीच की खाली जगह से नीचे नहीं गिर सकेगा।

स्पीड कैमरे को नहीं दे सकेंगे धोखा : वाहनों की गति सीमा को पकड़ने एक्सप्रेस-वे पर स्पीड कैमरे लगे हैं। वाहन चालकों को इन कैमरे की जगह पता है। जब वाहन चालक इन कैमरों वाली जगह से गुजरते हैं तो रफ्तार को कम कर देते हैं और कार्रवाई से बच जाते हैं। लेकिन चालकों को अब तेज रफ्तार में वाहन चलाकर कार्रवाई से बचना आसान नहीं होगा। वाहनों की तेज रफ्तार को पकड़े के लिए 12 हैंड हैंडल कैमरे दिए गए हैं। कर्मचारी किसी भी जगह पर इन कैमरों को लेकर खड़े हो जाएंगे और वाहनों की रफ्तार दर्ज करेंगे।

रंबल स्ट्रिप की बढ़ेगी संख्या : एक्सप्रेस वे पर तीस स्थानों पर रंबल स्ट्रिप लगी हैं। इन्हें बढ़ाकर पचास किया जाएगा। एक्सप्रेस वे पर होने वाले हादसों का बड़ा कारण चालक का नींद में आना है। रंबल स्ट्रिप से गुजरते समय लगने वाले हल्के झटकों से चालक की नींद टूट जाएगी और हादसों पर अंकुश लगेगा।

किनारे लगे क्रैश बीम बैरियर की ऊंचाई बढ़ेगी : ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे के दोनों किनारों पर क्रैश बीम बैरियर लगे हैं। कई जगहों पर बीम बैरियर की ऊंचाई 65 सेमी तक है। जबकि मानक के अनुसार तक यह 75 सेमी होनी चाहिए। जिस जगह पर बीम बैरियर की ऊंचाई कम है, उसे बढ़ाया जाएगा। क्षतिग्रस्त बीम बैरियर को बदला जाएगा।

दुरुस्त होगी फेंसिंग व चालान होगा प्रभावी : एक्सप्रेस वे के दोनों ओर लगी क्षतिग्रस्त तार फेंसिंग को दुरुस्त किया जाएगा। तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश के लिए दो टोल के बीच में दूरी तय करने में लगे समय से रफ्तार का आंकलन होगा। निर्धारित रफ्तार से तेज दौड़ने वाले वाहनों का चालान होगा।

लोकायुक्त के समक्ष भाजपा नेताओं ने रखा अपना पक्ष

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भाजपा ने लोकायुक्त से सरकारी स्कूलों में कमरे बनाने में भ्रष्टाचार की शिकायत की है। इस मामले में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को लोकायुक्त से मिलकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने मामले की जांच कराने की मांग की।

लोकायुक्त से मिलने के बाद तिवारी ने कहा कि भाजपा ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ नए स्कूल के नाम पर केवल सेमीस्ट्रक्चर कमरे बनवाकर बड़े स्तर पर किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत की है। लोकायुक्त ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

उन्होंने कहा कि आप सरकार ने शिक्षा के नाम पर लगभग दो हजार करोड़ का घोटाला किया है। झूठ की बुनियाद पर सत्ता की नींव रखने वाली केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों से वादे तो कई किए, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का विरोध करने का नाटक कर केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ईमानदारी का सपना दिखाया था। इसके विपरीत सत्ता में आने पर आप नेताओं ने झूठ व फरेब की राजनीति कर दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। नकारात्मक विचारों वाली भ्रष्ट सरकार ने दिल्ली में साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में भ्रष्टाचार व महिला विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दिया है। आप के कई नेताओं पर महिलाओं के साथ अभद्रता के कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली के लोगों को लगने लगा है कि उन्होंने आप पर विश्वास कर गलती कर दी है। यही कारण है कि नगर निगम चुनाव और लोकसभा चुनाव में आप के कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।

तिवारी ने कहा कि आज प्रदूषण से दिल्ली का दम घुट रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री समस्या हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। नई बसें लाने की बात कही गई, लेकिन 54 माह बीत जाने के बाद मात्र 25 बसें खरीदी गई हैं जबकि जरूरत 20 हजार बसों की है। लोकायुक्त से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी प्रत्युष कंठ, मीडिया सह-प्रभारी नीलकांत बख्शी, प्रवक्ता हरीश खुराना भी शामिल थे।